किन्नर कैलाश यात्रा का आगाज

पहले दिन 115 श्रद्धालुओं ने शुरू की आस्था की चढ़ाई

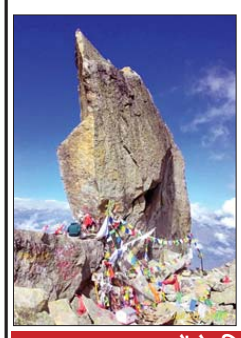

वरिष्ठ संवाददाता-रिकांगपिओ

किन्नर कैलाश यात्रा गुरुवार से सरकारी तौर पर शुरू हो गई है। किन्नौर प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पहले दिन 115 श्रद्धालुओं ने पवित्र किन्नर कैलाश के लिए आस्था की चढ़ाई की। प्रशासन की ओर से मंगलवार सुबह दस बजे खोले गए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल में 50 श्रद्धालुओं और ऑफलाइन पंजीकरण पोर्टल पर 57 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया बाकी एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के माध्यम से आठ श्रद्धालुओं ने शिवलिंग दर्शन के लिए रवाना हुए। पवित्र यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु को सुबह छह बजे तांगलिंग में पंजीकरण शिविर में रिपोर्ट कर ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।

■ ऑफलाइल-ऑनलाइन करवाएं पंजीकरण

175 श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगा स्लॉट

यह बताना आवश्यक हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर प्रतिदिन 175 श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट उपलब्ध रहेगा। एक दिन में केवल 125 ऑफलाइन पंजीकरण किए जाएंगे, शेष 75 सीटें एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन किन्नौर के कोटे के लिए आरक्षित हैं।

एक दिन में 375 श्रद्धालु कर पाएंगे भोले के दर्शन

एक दिन में 375 श्रद्धालुओं शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं । प्रशासन ने समूह में यात्रा करने और स्थानीय गाइडों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

भक्तों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य

किन्नर कैलाश यात्रा के लिए सभी भक्तों के लिए चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। यात्री अपने क्षेत्र के किसी भी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

सितंबर में होगी पूरक परीक्षा

दसवीं और 12वीं के विद्यार्थियों को राहत, तीन अगस्त से करें आवेदन

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-धर्मशाला



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (जमा दो) के छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। मार्च 2026 की वार्षिक परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुन: जांच (री-चेकिंग) के परिणाम आने के बाद, 376 छात्रों को सितंबर में होने वाली कंपार्टमेंट और आवश्यक श्रेणी सुधार परीक्षा में बैठने का विशेष मौका दिया गया है। इन लाभार्थियों में 10वीं कक्षा के 222 और 12वीं के 154 छात्र शामिल हैं। डा. शर्मा ने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तीन अगस्त, 2026 से शुरू हो जाएगी। छात्र अपने संबंधित स्कूलों के माध्यम से छह अगस्त, 2026 तक बिना किसी विलंब शुल्क के अपना फॉर्म भर सकते हैं। डा. राजेश शर्मा ने प्रदेश के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और संस्था प्रमुखों से विशेष आग्रह किया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी पात्र छात्रों के ऑनलाइन आवेदन समय रहते पूरे हो जाएं। कोई भी छात्र जानकारी के अभाव में इस मौके से वंचित न रहे।

पुराने प्रैक्टिकल अंक ही रहेंगे मान्य

बोर्ड अध्यक्ष ने छात्रों के संशय को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा में प्राप्त आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेसमेंट) और प्रायोगिक परीक्षा (प्रैक्टिकल) के अंक पहले की तरह ही मान्य रहेंगे। छात्रों को हिदायत दी गई है कि वे केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही आवेदन करें। अपूर्ण या किसी अन्य (ऑफलाइन) माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

लेट फीस लगेगी

अगर कोई छात्र चूक जाता है, तो वह 10 अगस्त, 2026 तक 1000 रुपए की लेट फीस के साथ आवेदन कर सकेगा। 10वीं कंपार्टमेंट, 10वीं आवश्यक सुधार और 12वीं कंपार्टमेंट श्रेणी के लिए परीक्षा शुल्क 700 रुपए निर्धारित किया गया है।

पानी की बोतलों के वितरण से पहले छात्रों का आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य

कार्यालय संवाददाता-शिमला

शिक्षा विभाग के निर्देश

विभाग ने बोतलों के वितरण, उपयोग और निगरानी के लिए मजबूत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों की जिम्मेदारियां तय करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, नियमित निगरानी करने और प्रत्येक स्तर पर रिकॉर्ड सधारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतलें बांटी जानी है। योजना को पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी पात्र विद्यार्थियों का आधार से सत्यापन (आधार लिंकिंग) सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों की सही पहचान हो और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या दोहराव को रोका जा सके। शिक्षा निदेशालय के अनुसार प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कुल 7,38,069 सुरक्षित पेयजल की बोतलों की आवश्यकता है। इसमें 72 अतिरिक्त बोतलें नमूना (सैंपल) स्टॉक के रूप में भी शामिल की गई हैं। 143 बीपीओ के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी उपलब्ध करवाई है।

छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन विश्वविद्यालय पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों और सीडीओई में स्नातक स्तर (यूजी) के सभी पात्र विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। आवेदन स्वीकृत करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। विद्यार्थी निर्धारित पोर्टल पर जाकर अपना नया पंजीकरण करेंगे और आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन प्रतियां अपलोड करेंगे।

दिव्यांगों को सम्मानित करेगी सरकार

असीम योजना के तहत विशेष व्यक्तियों को रोजगार देने वाले संस्थान भी होंगे पुरस्कृत

नगर संवाददाता- धर्मशाला

दिव्यांगजनों की प्रतिभा को नमन करने और उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण पहल की है। असीम (एएसईईएम) योजना के तहत घोषित ये राज्य स्तरीय पुरस्कार न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग कर्मचारियों और स्वावलंबी व्यक्तियों की मेहनत को सम्मानित करेंगे, बल्कि उन्हें 30 हजार रुपए तक की नकद प्रोत्साहन राशि और राज्य स्तरीय पहचान भी दिलाएंगे। इतना ही नहीं, यह पहल उन निजी व सरकारी संस्थानों और जिलों को भी पुरस्कृत करेगी जो दिव्यांगों को रोजगार देकर समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2026-27 के इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्हें तीन दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रदान किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार एवं संस्थान निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। चयनित विजेताओं को तीन दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार विजेता को 30 हजार रुपए की नकद राशि व प्रमाण पत्र और द्वितीय पुरस्कार विजेता को 20 हजार रुपए की नकद राशि व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

■ तीन दिसंबर को शिमला में सजेगा सम्मान समारोह

पांच प्रमुख श्रेणियां

पांच श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (बेस्ट एंप्लोयर), सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी (बेस्ट एंप्लोई विथ डिसअबिलिटी), सर्वश्रेष्ठ स्व-नियोजित दिव्यांग व्यक्ति (बेस्ट सेल्फ-एंप्लोय्ड), सर्वश्रेष्ठ संस्थान या विभाग (बेस्ट डिपार्टमेंट/ऑर्गनाईजेशन), सर्वश्रेष्ठ जिला (बेस्ट डिस्ट्रिक्ट) शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'जाखू मंदिर संजीवनी बूटी का रहस्य' पुस्तक का किया विमोचन



शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाखू मंदिर-संजीवनी बूटी का रहस्य पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भाषा एवं संस्कृति विभाग के पूर्व सहायक निदेशक एवं प्रदेश किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता त्रिलोक सूर्यवंशी ने लिखी है। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस पुस्तक से श्रद्धालु और पर्यटकों को मंदिर की जानकारी के साथ-साथ शिमला के इतिहास व संस्कृति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही शिमला के विरासत भवनों, अन्य धार्मिक स्थलों तथा ऐतिहासिक स्थलों का भी विस्तार से अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। इस अवसर पर लेखक की पत्नी माया सूर्यवंशी, जगमोहन शर्मा, पूर्ण चंद तथा अजय भारद्वाज उपस्थित थे

पेंशनरों की लंबित मांगे जल्द पूरी करें

शिमला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को शिमला में शहरी विकास विभाग के निदेशक डा. नीरज कुमार से मुलाकात कर शहरी स्थानीय निकायों के करीब 2300 पेंशनरों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान निदेशक शहरी विकास विभाग डा. नीरज कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1994 और संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप आगामी वर्ष 16वें वित्त आयोग के लागू होने के बाद आवश्यक प्रावधानों को भी कार्यान्वित किया जाएगा।

भूकंप से पुलों-भवनों को बचाने पर रिसर्च

मंडी आईआईटी के वैज्ञानिक कर रहे शोध

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-मंडी

मंडी आईआईटी में भूकंप से पुलों और भवनों को बचाए रखने पर रिसर्च की जा रही है। इसके साथ ही भूकंप से पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। मंडी आईआईटी भूकंप के दौरान भवनों एवं पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा और पुराने एवं क्षतिग्रस्त ढांचों की भूकंपीय संवेदनशीलता को जानने के लिए शोध कर रही है। आईआईटी मंडी की सिग्मा-एचवीआर लैब में भूकंप इंजीनियरिंग, भूकंप विज्ञान तथा भूकंपीय जोखिम विश्लेषण के क्षेत्र में शोध किया जा रहा है। आईआईटी मंडी में भूकंप से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य चल रहे हैं। शोध मुख्य रूप से भूकंप रोधी संरचनाओं, भूकंपीय जोखिम, संरचनाओं की संवेदनशीलता तथा भूकंप के बाद उनकी कार्यक्षमता पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भूकंप की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि भूकंप आने पर भवनों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही इन्हें अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए बेहतर रेट्रोफिटिंग और जोखिम-आधारित निर्णय प्रणाली का विकास किया जा रहा है।

टीम वर्क से हो रहा काम

मंडी आईआईटी के विशेषज्ञ डा. महेशरेड्डी गाडे एवं डा. धन्या जे के नेतृत्व में यह शोध समूह भौतिकी आधारित भूकंप सिमुलेशन विकसित कर रहा है। इसके साथ ही मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके भूकंपीय जोखिम का आकलन भी किया जा रहा है।

नुकसान भूकंप की तीव्रता पर निर्भर नहीं

नुकसान केवल भूकंप की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। नुकसान के लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं। भूकंप का केंद्र कितनी गहराई पर है। उपकेंद्र आबादी से कितनी दूरी पर है। स्थानीय मिट्टी की स्थिति और भवनों की गुणवत्ता तथा निर्माण मानक सहित जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करता है।

मांगें पूरी करवाने पर अड़े शिक्षक

शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर पांच दिन से क्रमिक अनशन लगातार जारी है। प्राथमिक शिक्षक संघ जिला मंडी के अध्यक्ष बाबूराम कौंडल का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं कर देती, तब तक उनका यह आंदोलन और क्रमिक भूख हड़ताल अटूट रूप से जारी रहेगी। शिक्षकों के इस भारी हुजूम में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धरना स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा करते हुए यह भरोसा दिलाया कि यदि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम में संशोधन की आवश्यकता हुई तो संशोधन किया जाएगा।

वन विभाग में रेंज फोरेस्ट ऑफिसर और डिप्टी रेंजर के 20 पद समाप्त

वरिष्ठ संवाददाता-शिमला

■ प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना, वर्ष 2017 के आदेशों में संशोधन

राज्य में वन विभाग ने बीस पदों को समाप्त कर दिया है। इनमें वन विभाग के कानूनी मामलों के लिए सृजित किए रेंज फोरेस्ट ऑफिसर के दस और इतने ही पद डिप्टी रेंजर के शामिल है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी गुरुवार को जारी कर दी गई है। वर्ष 2017 में सरकार की ओर से जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं में संशोधन करने के उपरांत यह कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार सितंबर 2017 में वन विभाग में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (लीगल) के 10 पद सृजित किए थे और इन पर तैनाती की गई है। इस अधिसूचना में आंशिक संशोधन करने हुए विभाग के बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, नाहन, रामपुर, शिमला और सोलन सर्किल में रेंज फोरेस्ट ऑफिसर (लीगल) का पद समाप्त किया गया है। डिप्टी रेंजर (लीगल) के दस पद समाप्त किए गए हैं। इनमें बिलासपुर सर्किल के बिलासपुर डिवीजन, सोलन के नालागढ़ डिवीजन, चंबा के भरमौर, धर्मशाला के नूरपुर, हमीरपुर के ऊना, मंडी के करसोग, नाहन के राजगढ़ और पांवटा तथा शिमला सर्किल के शिमला (रूरल) और चौपाल वनमंडल में एक-एक पद शामिल है।

वन विभाग के क्लास फोर ने वनरक्षक पद पर मांगी प्रोमोशन

शिमला। प्रदेश में वन विभाग में कार्यरत तीन सौ के करीब क्लास फोर कर्मचारियों ने वन रक्षक के पद पर प्रोमोशन मांगी है। इसी को लेकर बुधवार को कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीसीसीएफ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वनरक्षक के पदों पर एकमुश्त पदोन्नति प्रदान करने का आग्रह किया है। पीसीसीएफ ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि सहानुभूति पूर्वक विचार कर आगामी कदम फैसला लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार वन विभाग में कार्यरत फोर्थ क्लास कर्मचारियों के लिए प्रोमोशन की मौजूदा समय में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके चलते ऐसे कर्मचारी 25 से 30 वर्ष सेवाएं देने के उपरांत भी बिना प्रोमोशन के रिटायर हो रहे है।

बिजली बोर्ड में टीमेट को मिला प्रोमोशन का तोहफा

वरिष्ठ संवाददाता-शिमला

■ 15 दिन के भीतर नई जगह ज्वाइन करने के निर्देश



राज्य बिजली बोर्ड के फील्ड तकनीकी स्टाफ के आठ टीमेट को पदोन्नत कर सहायक लाइनमैन बनाया गया है। डीपीसी की सिफारिश के आधार पर बोर्ड की ओर से इन कर्मचारियों को नियमित आधार पर प्रोमोशन दी है। लिहाजा प्रबंधन ने इन सभी कर्मचारियों को 15 दिन के भीतर अपनी ज्वाइनिंग देने को कहा है। पदोन्नति का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मिलेगा। ईएस सर्किल टूटू के डिप्टी चीफ इंजीनियर के हवाले से जारी आदेश के तहत सौरव, सुनील कुमार, अभिषेक भाटिया, अनिल कुमार, हरि सिंह, रमन कुमार, मनजीत और कुलदीप कुमार को एएलएम पद पर पदोन्नत किया गया है। सौरव को कुनिहार से शिमला, सुनील कुमार को कुनिहार से नाहन और अभिषेक भाटिया को सोलन से नाहन में नियुक्ति दी है। इसी तरह अनिल कुमार को नाहन, हरि सिंह सोलन, रमन कुमार को नालागढ़ से नाहन, मनजीत को नाहन तथा कुलदीप कुमार को ईएस डिवीजन शिमला में ही तैनात किया गया है।

186 शिक्षकों को पदोन्नति जल्द

शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा अब हेडमास्टर पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न स्कूलों में तैनात 186 शिक्षकों को हैडमास्टर बनाया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को शिक्षकों की लंबित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि टीजीटी से पदोन्नत प्रवक्ता और प्रवक्ता संवर्ग के उन शिक्षकों की वर्ष 2026 की पदोन्नति के लिए वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की लंबित एसीआर पहली अगस्त तक हर हाल में शिक्षा निदेशालय पहुंचनी चाहिए।

एचआरटीसी में सब-इंस्पेक्टर चालकों को पदोन्नति का लाभ

कार्यालय संवाददाता-शिमला

इन स्थानों पर तैनाती

इनमें बैजनाथ, रामपुर, मंडी, बंजार, जोगिंदरनगर, सुंदरनगर, तारादेवी, सोलन, रिकांगपिओ, हमीरपुर, कुल्लू, जालंधर, धर्मशाला, ऊना, चंबा, केलांग और धर्मपुर सहित विभिन्न इकाइयों में नई तैनातियां की गई हैं।



एचआरटीसी मुख्यालय शिमला ने गुरुवार को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर सब इंस्पेक्टर और चालकों की पदोन्नति के आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार कुल 25 कर्मचारियों को इंस्पेक्टर के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है। इनमें 13 सब इंस्पेक्टर और 12 चालक शामिल हैं। पदोन्नत कर्मचारियों को पे.मैट्रिक्स लेवल-9 के तहत 35,600 से 1,12,800 के वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा। जारी आदेशों के अनुसार कई अधिकारियों को वर्तमान स्टेशन पर ही पदोन्नति दी गई है, जबकि कुछ का स्थानांतरण अन्य डिपो और इकाइयों में किया गया है। एचआरटीसी प्रबंधन का मानना है कि इन पदोन्नतियों से निगम की निरीक्षण व्यवस्था और परिचालन कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी।



अनुराग ठाकुर

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-हमीरपुर

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63 किलोमीटर) नई रेललाइन परियोजना का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किए जाने के कारण प्रभावित हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार लागत साझेदारी व्यवस्था के तहत राज्य सरकार को कुल 2,910 करोड़ रुपए का अंशदान देना था, जिसके मुकाबले अब तक केवल 847 करोड़ रुपए ही जमा किए गए हैं। इस प्रकार 2,063 करोड़ रुपए की राशि अभी भी बकाया है, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन और भुगतान प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिलासपुर-बेरी खंड के लिए भूमि अधिग्रहण एवं भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिससे निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में आधुनिक रेल अवसंरचना के विस्तार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर खंड के लिए भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है।

2,063 करोड़ जमा न करवाने से भानुपल्ली बिलासपुर-बेरी रेल परियोजना प्रभावित

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN:L65910KL1992PLC006623,
RegisteredOffice:W-4/638A,ManappuramHouse,
P.O.Valapad,Thrissur-680567,Kerala,India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 17/08/2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

कांगड़ा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, 0138470700002714, 2943, 3109, 3875, 0138470730003039, 3205, 3537, 6884, 6886, 6888, 6890, 6891, धर्मशाला रोड़ कांगड़ा, 0135950700007947, 7948, 8495, 8756, 8857, 8898, 0135950730011609, 1711, 6310, योल कैंट, 0139420700002538, 2914, 2925, 0139420730003584, 5730, 5731, 5732, 5733, मंडी, नेर चौक सुंदरनगर, 0139010700002923, 3165, 3330, 3433, 3491, 3601, 3604, 3612, 3684, 3698, 3699, 0139010730003380, 3956, 6311, 6312, 6313, 6314, रामनगर मंडी, 0137800730001921, 2015, 3977, 3980, सुंदर नगर-एपी, 0136030700004587, 0110, 0174, 0399, 0449, 0493, 0515, 0136030730005972, 7243, 8275, 8304, 8305, 1063, 1065, 1066, 1071, 1072, 1074, 1078, सोलान, बद्दी एच.पी., 0135990700013708, 4152, 4513, 4872, 4904, 5227, 5249, 5262, 5295, 5317, 5484, 5526, 5537, 5591, 5616, 5728, 5897, 6133, 6149, 6151, 6155, 6178, 6219, 6250, 6277, 6290, 6294, 6392, 6424, 6475, 6476, 6533, 6550, 6609, 6823, 6890, 6915, 6925, 6933, 6974, 7056, 7147, 7230, 7253, 0135990730006779, 7068, 7584, 7713, 7718, 8344, 8445, 8489, 8492, 9718, 9754, 0036, 0076, 0595, 2395, 2485, 2646, 0111, 0148, 0149, परवानू, 0127190700007602, 8258, 8314, 8455, 8465, 8504, 8514, 0127190730004899, 5438, ठाकुर कॉम्प्लेक्स सोलन, 0135150700011655, 1875, 2171, 2506, 2517, 2645, 2737, 2785, 2802, 2876, 2918, 2976, 3087, 3168, 3180, 4038, 4041, 4042, 0135150730011580, 1581, 2662, 3943, 6603, 0115, उना, अम्ब उना एच.पी., 0138770700002447, 0138770730001829, हमीरपुर रोड उना, 0135130700008058, 0135130730005622, 6119, 7921, मेहतपुर बस्देहरा, 0138550700003239, 0138550730001763, संतोखगढ़ ऊना हिमाचल प्रदेश, 0138710700003733, 4031, 4036, 4045, 0138710730002300, 4103, 4104, 4105, 4107,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए ज्यादा जानकारी के लिए कृपया 9911809139 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु

पंचायती राज चुनाव में 80, शहरी निकाय में 70.14 प्रतिशत

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सौंपी रिपोर्ट

वरिष्ठ संवाददाता-शिमला



आम चुनाव-2026 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते राज्य निर्वाचन आयुक्त

हिमाचल में इसी वर्ष हुए पंचायती राज चुनावों में करीब 80 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। जबकि शहरी निकाय चुनावों में मत प्रतिशतता 70.14 रही है। इसके अलावा राज्य में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2026 में यह 54.55 लाख पहुंच गई। लिहाजा यह आंकड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की मजबूत भागीदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरुवार को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में यह आंकड़े सामने आए है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन में राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची से प्रदेश के स्थानीय निकायों की आमसभा चुना 2026 की रिपोर्ट प्राप्त की। यह रिपोर्ट मई 2026 में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनावों से संबंधित है। इस रिपोर्ट में चुनाव प्रक्रिया की कार्य योजना, तैयारियों और संचालन का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें चुनावों के सफल आयोजन से जुड़े प्रशासनिक उपायों, महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं, विभिन्न चुनौतियों और प्रमुख उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, परिसीमन के बाद राज्य की स्थानीय शासन व्यवस्था का दायरा बढ़ा है। वर्ष 2021 में ग्राम पंचायतों की संख्या 3,615 थी, जो 2026 में बढ़कर 3,758 हो गई। इसी प्रकार पंचायत समितियों की संख्या 81 से बढ़कर 92 हो गई है। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायतों की संख्या 27 से बढ़कर 39 तथा नगर निगमों की संख्या पांच से बढ़कर आठ हो गई है। राज्यपाल ने कहा कि चुनावों का सफल आयोजन हिमाचल प्रदेश की जनता, राजनीतिक दलों और चुनाव से संबंधित अधिकारियों की लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

काम से खुश

राज्यपाल ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सराहना की। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट के प्रकाशन की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, प्रशासकों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में कार्यरत एवं आम नागरिकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज साबित होगा।

एचपीपीएससी अध्यक्ष ने राज्यपाल को प्रस्तुत की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट



शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने गुरुवार को लोक भवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को आयोग की वर्ष 2025-26 की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर आयोग के सदस्य कर्नल राजेश कुमार शर्मा, डा. पवनेश शर्मा, प्रो. ममता मोक्टा, राखिल काहलों, आयोग की सचिव निवेदिता नेगी तथा अतिरिक्त सचिव छवि नांटा भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने आयोग के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने कार्यकुशलता बढ़ाने, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और डिजिटल युग के अनुरूप तकनीकी समाधानों को अपनाने के लिए कई संस्थागत सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सुशासन को बढ़ावा देने के प्रति आयोग की सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है